





		<div> <div> Cosmo First Ahead Always </div> <div> RESILIENT AND RISING </div> </div>		
<div> AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS (Rs in Crores) </div>				
<div> <div>Figures represent FY24-25</div> <div> 44% EBITDA </div> </div>		<div> <div>114% PAT </div> </div>		
Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2025 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited
Revenue from operations	746	641	2,895	2,587
Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	85	67	362	251
Profit before tax for the period	33	18	163	72
Net profit after tax for the period	27	15	133	62
Basic earnings per share (of Rs 10 each) (not annualised)	10.5	5.9	51.5	24.0
<div> Notes: <ol style="list-style-type: none"> The Board of Directors had recommended dividend of Rs. 4/- per equity share for the financial year FY 24-25 subject to approval of shareholders in annual general meeting. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated and standalone financial results for the quarter and year ended on 31st March 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.cosmofirst.com). The financial results can also be accessed by scanning below QR code. </div>				
<div> New Delhi 20th May 2025 </div>		<div> <div>ASHOK JAIPURIA</div> CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR </div>		
<div> <div>COSMO FIRST LIMITED</div> <div> Regd. Off: 1st Floor, Uppal's Plaza, M-6, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950, E-mail: investor.relations@cosmofirst.com, Website: www.cosmofirst.com </div> </div>		<div> <div> <div>“</div> <div> Driving momentum through perseverance and growth, our journey embodies resilience and upward progress. With strategic focus and dedication, we continue to achieve success, creating lasting value for stakeholders. </div> <div>”</div> </div> <div> <div>SCAN HERE</div> <div>For detailed results</div> </div> <div>  </div> </div>		
<div> <div>OUR BUSINESSES:</div> <div> <div>  COSMO FILMS Engineered to Enhance </div> <div>  COSMO PLASTECH Designed to protect </div> <div>  COSMO SUNSHIELD Solve + Protect + Finance </div> <div>  COSMO SPECIALTY CHEMICALS We Value Resilience </div> <div>  Zigly For Happy Pets </div> </div> </div>				



इण्डियन ओवर्सिज़ बैंक
मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा साहेब, चेन्नै - 600002
फोन नं. 044- 2888 9312

सीटीएस 2010 मानक सुस्था लिखितों के मुद्रण हेतु सुस्था प्रिंटर्स का पैनलीकरण एवं दर अनुबंध का निर्धारण

सीटीएस 2010 मानक सुस्था लिखितों के मुद्रण के लिए आदेशों की अनुमोदित सूची में शामिल स्वाम और चार प्रिंटर्स से सुस्था प्रिंटर्स के पैनलीकरण और दर अनुबंध के निर्धारण के लिए निविदा प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस लिंक <https://lobtenders.auctiontiger.net/EPROC/> के जरिए ई-निविदाएं हेतु आवेदन भर सकते हैं या www.iob.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

दस्तावेज शुल्क, वापसी योग्य नहीं	₹. 2,000/- (जीएसटी सहित)
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	13.06.2025 को शाम 15.00 बजे तक

बैंक के पास इस निविदा दस्तावेज में संश्लेषित निर्माण और शर्तों को बदलने/संशोधित करने का अधिकार है, जिसे लिचें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक



केनरा बैंक Canara Bank
क्रेडिट और संचालन
संयोजित सेवाएं

क्षेत्रीय कार्यालय
सी3, दूसरा तल, सेक्टर 1, नोएडा,
उत्तर प्रदेश - 201301,
फोन: 0120-2524896

दिनांक : 08.05.2025

संदर्भ सं. 88857730000084
प्रति उधारकर्ता/गारंटोरों/बंधककर्ता:

उधारकर्ता (वर्तमान पता) : श्री संजय कुमार दास पुत्र कानू चरण दास,
फ्लैट सं. 04113, सीएचएआई-IV, एटीएस ग्रीन पैराडाईस, ग्रेटर नोएडा-210203 उत्तर प्रदेश

उधारकर्ता (संपत्ति पता) : श्री संजय कुमार दास पुत्र कानू चरण दास,
फ्लैट सं. टी-05034, टॉवर-6, टाईप-बी, तीसरा तल, एटीएस ग्रीन पैराडाईस, मापक 2150 वर्ग फुट, स्थित प्लॉट सं. जीएच-03, सेक्टर-सीएचआई 4, ग्रेटर नोएडा, जिला जी बी नगर-201310

उधारकर्ता (स्थायी पता) : श्री संजय कुमार दास पुत्र कानू चरण दास,
कतालिया सरदारपारा, मकरदाह, डॉमजूर हावड़ा, वेस्ट बंगाल-711409

गारंटोर (वर्तमान पता) : श्रीमती शताब्दी गंगोपाध्याय पत्नी संजय कुमार दास
फ्लैट सं. 04113, सीएचएआई-IV, एटीएस ग्रीन पैराडाईस, ग्रेटर नोएडा-210203 उत्तर प्रदेश

गारंटोर (स्थायी पता) : श्रीमती शताब्दी गंगोपाध्याय पत्नी संजय कुमार दास
कतालिया सरदारपारा, मकरदाह, डॉमजूर हावड़ा, वेस्ट बंगाल-711409

गारंटोर (संपत्ति पता) : श्रीमती शताब्दी गंगोपाध्याय पत्नी संजय कुमार दास
फ्लैट सं. टी-05034, टॉवर-6, टाईप-बी, तीसरा तल, एटीएस ग्रीन पैराडाईस, मापक 2150 वर्ग फुट, स्थित प्लॉट सं. जीएच-03, सेक्टर-सीएचआई 4, ग्रेटर नोएडा, जिला जी बी नगर-201310

विषय : वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (तत्पश्चात "अधिनियम" से संदर्भित) की धारा 13(8) के तहत पुनर्खरीद के अधिकार के लिए सूचना

अधोहस्ताक्षरी कैनरा बैंक, मोरना शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, (तत्पश्चात "प्रच्युत ऋणदाता" से संदर्भित), अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है, एतद्वारा सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के सहपठित अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, आप सभी के लिए निम्न लिखित रूप में इस सूचना को जारी करता है:

जैसा कि आप जानते हैं, प्रच्युत ऋणदाता ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत — 01.03.2025 (मांग सूचना की दिनांक) को उधारकर्ता श्री संजय कुमार दास पुत्र कानू चरण दास (इसके बाद "उधारकर्ता" से संदर्भित) और श्रीमती शताब्दी गंगोपाध्याय पत्नी संजय कुमार दास (इसके बाद "गारंटोर" से संदर्भित) को मांग सूचना जारी की, जिसमें रुपये 32,23,444/- (रुपये बीस लाख तैसी हजार चार सौ चौवालीस मात्र) की राशि और उस पर ब्याज का भुगतान 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

चूंकि, उधारकर्ता/फर्म, बंधककर्ता और गारंटोर (उपरोक्त वर्णित नाम) ने उपरोक्त मांग सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने 06.05.2025 को कब्जा सूचना में वर्णित प्रच्युत परिसंपत्तियों का प्रतिकात्मक/भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, उक्त प्रतिकात्मक/भौतिक कब्जे की सूचना 08.05.2025 (प्रकाशन की दिनांक) को बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी (स्थानीय भाषा में समाचार पत्र का नाम) और बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम) में उचित रूप से प्रकाशित की गई थी।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा के प्रावधानों के अनुपालन में, सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ, आप सभी को इस सूचना कि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, 08.05.2025 तक की देनदारी रुपये 31,25,492/- (रुपये इक्कीस लाख पच्चीस हजार चार सौ बानबे मात्र) का भुगतान करके, साथ ही भविष्य का ब्याज, लागत और व्ययों का पूरा भुगतान कर प्रच्युत परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने और पुनः दावा करने का अंतिम और आखरी अवसर दिया जाता है, जो प्रच्युत ऋणदाता के कब्जे में है, अन्यथा अधिनियम के तहत बिक्री सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जिसमें निम्न वर्णित लिखित तरीकों से या एक को प्रच्युत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए निविदा किया जाएगा:

1. समान प्रच्युत परिसंपत्तियों से निवटने वाले व्यक्तियों से या संपत्तियों को खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से उद्धरण प्राप्त करके; या

2. जनता से निविदाएं आमंत्रित करके; या

3. सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके जिसमें ई-नीलामी मॉड शामिल है, या

4. निजी संकट द्वारा;

5. अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार आप किसी भी समय बिक्री सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक से पहले प्रच्युत परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के हकदार हैं, अन्यथा आपके द्वारा धारा 13(8) के अनुसार बंधक संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

यह प्रच्युत ऋणदाता के पास विषय अधिनियम/या किसी अन्य लागू कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाह्रह के बिना है।

भवदीय,
कैनरा बैंक
प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सेक्टर-24 नोएडा शाखा, चौत मोड़, सरकारी ईंट स्कूल के सामने, सेक्टर-22, नोएडा, 201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-24 नोएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 03-01-2025 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं : राम सेवक गोस्वामी पुत्र श्री राजा राम गोस्वामी को, सूचना में अंकित राशि ₹. 2,06,581.96/- (रुपये दो लाख छह हजार पाँच सौ इक्यासी एवं छियानबे पैसे मात्र + लागूयोग्य ब्याज+ विधिक व्यय) (जो 03-01-2025 के अनुसार देय मूलधन तथा ब्याज का अम्यावेदन करता है) तथा पूर्ण भुगतान होने तक भावी ब्याज तथा अन्य शुल्कों के साथ दंडिक ब्याज इत्यादि छोड़कर उक्त सूचना की तिथि को देय ब्याज तथा अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता बैंक की संपूर्ण बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 14 मई 2025 को, (सौकेतिक अधिग्रहण) कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, ₹. 2,06,581.96/- (रुपये दो लाख छह हजार पाँच सौ इक्यासी एवं छियानबे पैसे मात्र+लागूयोग्य ब्याज+ विधिक व्यय) (जो 03-01-2025 के अनुसार देय मूलधन तथा ब्याज का अम्यावेदन करता है) तथा राशिपर नियत ब्याज हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 24 नोएडा शाखा के प्रभारधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफोएसि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सं.- संपत्ति सं. 38सी धारक आवासीय संपत्ति का समतुल्य बंधक, जो ब्लॉक- एसके, द्वितीय तल पर, सेक्टर- 122, नोएडा- 201316 में स्थित है।

तिथि: 14/05/2025 (प्राधिकृत अधिकारी)

स्थान: नोएडा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया



पंजाब नेशनल बैंक
.....गोरे से का प्रतीक
A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING
.....the name you can BANK upon!

HEAD OFFICE: PLOT NO. 4, SECTOR-10, DWARKA NEW DELHI-110075

Date: 03.04.2025

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS, PURSUANT TO PROCEEDINGS CONDUCTED AT HEAD OFFICE ON 15.03.2025

M/s Amrapali Smart City Developers (P) Limited (Rs. 95.13 crore)

Circle SASTRA / Zonal SASTRA: New Delhi / New Delhi

Date of NPA: 29.01.2017

In terms of RBI Master Circular no. DBR, No. CID.BC.22/20.16.003/2015-16 dated July 01, 2015, Committee for Identification of Wilful Defaulters issued Show Cause Notice dated 15.11.2021 to following persons mentioning the grounds on the basis of which they are identified as wilful Defaulter:-

1. M/s Amrapali Smart City Developers (P) Limited (Borrower)

2. Sh. Anil Kumar Sharma (Director/Guarantor)

3. Sh. Shiv Priya (Director/Guarantor)

Vide Show Cause Notice, the above-named persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they should not be classified as wilful defaulter. Representation dated 05.12.2021 was received against Show Cause Notice, from Sh. Anil Kumar Sharma through Advocate Manoj Singh & Associates.

Based on the representations received, the Identification Committee decided to grant the borrower and its related persons an opportunity for a personal hearing, scheduled for 25.05.2022. Representations dated 27.06.2022, were submitted by Sh. Shiv Priya, against the personal hearing notice.

During the hearing, the Committee noted that directors Sh. Anil Kumar Sharma and Sh. Shiv Priya were incarcerated and unable to attend, which was deemed contrary to the principles of natural justice. Consequently, the Identification Committee decided to place the wilful default proceedings in abeyance in light of the directors' inability to participate in the personal hearing. As per the RBI's new Master Directions issued on July 30, 2024, the Review Committee for wilful defaulters will provide an opportunity for a personal hearing. Hence, Identification Committee in its meeting held on 08.01.2025 after considering the case and material held on record, representation, identified the borrower and its related parties as wilful defaulters and issued Order dated 14.01.2025 vide which, the identified persons were given opportunity to make a representation, if they so desire, to the Bank within 15 days from receipt of Order, as to why they should not be classified as wilful defaulter on the following grounds:-

Capacity To pay

As per the CA certificate dated 26.05.2015, the directors/guarantors possess sufficient net means to repay the bank's dues. However, despite having the financial capacity, they are not fulfilling their repayment obligations to the bank.

Name	Net Means	CA Certificate date
Sh. Anil Kumar Sharma	Rs.740.39 Crore	26.05.2015
Sh. Shiv Priya	Rs.373.48 Crore	26.05.2015

Diversion of Funds

Hon'ble Supreme Court in the course of hearing has pointed out diversion of funds of more than Rs.2765 crores by the Amrapali Group.

Forensic Audit Report which is part of Supreme Court order summarizes: i) Non genuine purchases from suppliers ii) Bogus expenses and cash surrendered in Income Tax search iii) Double booking of expenses iv) Unsupported cash payments- wages etc v) Gold bar purchased from Yashika Diamonds. vi) Foreign investment (violation of FEMA) vii) Companies created solely for purpose of routing funds and building assets viii) Misuse of funds by Directors (i.e. salary, professional fees, use of luxury cars etc) ix) Sale of flats at lower price (undervalued transactions) x) Group investment in other projects

Representation of Sh. Shiv Priya (Director) dated 24.02.2025 was received against identification Order dated 14.01.2025. In accordance with the RBI Master Directions No. DoR.FIN.REC No.31/20.16.003/2024-25 dated 30.07.2024, the borrower and its related parties were granted an opportunity for a personal hearing before the Review Committee on 15.03.2025. However, neither the borrower and its related parties attended personal hearing nor any communication received from them regarding their absence. The Review Committee deliberated over the facts, representations received of the case as under:-

Deliberation of the Review Committee

The representative Sh. Shiv Priya made a representation against the bank's order dated 14.01.2025, which identified him as a wilful defaulter. He claimed that the bank did not verify the facts properly and issued the order under preconceived notions. He argued that the bank should not have used the Forensic Audit Report from W.P. (C) No. 940/2017, as per the engagement letter dated 10.10.2018.

The Review Committee noted bank's stand that the order was issued after thorough verification of facts and evidence. The use of the Forensic Audit Report was justified as it was part of the Supreme Court-mandated investigation in W.P. (C) No. 940/2017. The bank denied any preconceived notions and stated that the order was based on credible findings. The bank clarified that the Forensic Audit Report was not used against the directions of the Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No. 940/2017. The report-highlighted instances of fund diversion, non-genuine purchases, bogus expenses, and other fraudulent activities, which justify the classification of the account as a wilful defaulter.

The Representative also claimed a lack of access to documents due to custody since 11.10.2018, making it difficult to provide a detailed representation. He pointed out that the writ petition is still pending, and the Forensic Audit Report has not attained finality, making the bank's order premature. He asserted that the bank was misled by the initial Forensic Audit Report, which should not have been used as per the mandate, and the matter is still under investigation.

The Review Committee noted that Sh. Shiv Priya acknowledged that documents were submitted to the Forensic Auditor but emphasized that the findings of the Forensic Audit Report, which highlight fund diversion and fraudulent activities, remain uncontested. It was noted that while Sh. Shiv Priya claims a lack of access to documents due to custody, the Forensic Audit Report and other evidence used in the wilful default proceedings were obtained by the bank through lawful means and not against the Supreme Court directives. The bank asserted that the pendency of the writ petition did not preclude the bank from taking action based on the findings of the Forensic Audit Report. The report has been duly considered, and the order was issued after careful evaluation of all evidence.

It was denied that the borrower was misled by the Forensic Audit Report. The report was prepared as per the Supreme Court's mandate and highlighted clear instances of fund diversion and fraudulent activities, which justify the wilful default classification.

The Representative further stated that his group company has fully discharged liabilities in several projects, including Amrapali Zodiac, Amrapali Sapphire, Amrapali Grand, Amrapali Eden Park, Amrapali Green, and Amrapali Village. Phase I and II. He mentioned that the group has taken loans of approximately ₹2800 Crore and repaid around ₹2300 Crore, including principal and interest, indicating no ill-will.

The Review Committee noted that while Sh. Shiv Priya claims full discharge of liabilities in certain projects, the bank noted that these claims do not negate the fact that other accounts were classified as NPA due to non-payment of dues. It was emphasized that the borrower failed to regularize the account despite repeated intimations and follow-ups.

Shri Shiv Priya denied any intention to default, stating that the company repaid interest and quarterly instalments until FY 2016-2017, but cash flow was impacted due to uncontrollable reasons. He confirmed that all required documents were submitted to the Forensic Auditor appointed by the Supreme Court in W.P. (C) No. 940/2017.

The Review Committee noted the assertion that failure to discharge obligations was not intentional, does not diminish the fact that the borrower has failed to meet its financial obligations, which were due in accordance with the terms of the loan agreement. Therefore, the bank is within its rights to proceed with the "Wilful Default" proceedings as per the provisions of the applicable laws and regulations.

Based on the facts and evidence, the bank found the explanations provided in the representation unsatisfactory and insufficient to refute the allegations of wilful default.

The Representative highlighted that the DRT and the Hon'ble Supreme Court have deemed Amrapali Group's projects economically viable, and based on this economic viability, the banks have financed their projects and disbursed loans.

The Review Committee noted that borrower and directors primarily outlined their submissions and the orders passed by the Hon'ble Supreme Court & DRT but failed to rebut the points of wilful default mentioned in the SCN dated 15.11.2021.

The Representative stated that Supreme Court authorized the DRT Delhi to auction Amrapali Group's assets, which were valued as economically viable by the Ld. Receiver.

The Review Committee noted that while the Supreme Court authorized the auction of Amrapali Group's assets, this does not absolve the borrower of the wilful default allegations. The Forensic Audit Report and other evidence clearly indicate fund diversion and fraudulent activities.

The Representative cited the RBI Circular dated 01.07.2014 and the Supreme Court's judgment in SBI v. Jah Developers (P) Ltd., arguing that no prior hearing was provided, violating natural justice. He requested a personal hearing, stating that denial would violate natural justice and that the order was based on a Forensic Audit Report that should not have been used.

The Review Committee noted that as per the RBI's new Master Directions, the Review Committee for wilful defaulters have provided an opportunity for a personal hearing to borrower and its related parties on 15.03.2025. Despite being given an opportunity to present their case, no one appeared before the Review Committee.

The Review Committee noted that all earlier letters/representations of the borrower and its related parties have been considered by the Bank. It was observed that borrower and its related parties failed to provide any concrete evidence to disprove allegations of wilful default.

ORDER OF THE REVIEW COMMITTEE FOR DECLARATION OF WILFUL DEFAULTERS:

The Review Committee chaired by the MD & CEO of the Bank and the Directors of the Bank as members, after due consideration of the above said facts and evidence on record, in its meeting held on 15.03.2025, concurred with the order of the Identification Committee and found that the captioned borrower and its related parties are responsible for the above events of wilful default, which constitute cogent ground of being declared as 'Wilful Defaulter' in terms of extant Bank guidelines issued in consonance with the RBI guidelines/ Master Directions no. DoR.FIN.REC No.31/20.16.003/2024-25 dated July 30, 2024.

S.No	Name	Designation/Status	Charges
1	M/s Amrapali Smart City Developers (P) Ltd.	Borrower	Diversion of Funds
2	Shri Anil Kumar Sharma	Director	
3	Shri Shiv Priya	Director	
4	Shri Ajay Kumar	Director	

The Committee directed to issue the Order accordingly and to serve the same upon the borrower and its related persons.

Review Committee-I constituted in consonance with the RBI directives comprises of the following members:

i. Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank (Head of Committee)

ii. Share Holder Director

iii. Share Holder Director and

iv. Chief General Manager, SASTRA Division, HO (Invitee)

The Review Committee-I, has authorized the undersigned to send this **ORDER OF THE COMMITTEE FOR REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS** under his signature.

KRISHNA PRATAP SINHA
Deputy General Manager



Cosmo First
Ahead Always



RESILIENT AND RISING



AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS



(Rs in Crores)

Figures represent FY24-25

44%
EBITDA

114%
PAT

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2025 Unaudited	31.03.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited
Revenue from operations	746	641	2,895	2,587
Earning before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	85	67	362	251
Profit before tax for the period	33	18	163	72
Net profit after tax for the period	27	15	133	62
Basic earnings per share (of Rs 10 each) (not annualised)	10.5	5.9	51.5	24.0

Notes:

1

The Board of Directors had recommended dividend of Rs. 4/- per equity share for the financial year FY 24-25 subject to approval of shareholders in annual general meeting.

2

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated and standalone financial results for the quarter and year ended on 31st March 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.cosmofirst.com).

3

The financial results can also be accessed by scanning below QR code.

New Delhi
20th May 2025

ASHOK JAIPURIA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

COSMO FIRST LIMITED
Regd. Off: 1st Floor, Uppal's Plaza, M-6, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949, Fax: 011-49494950, E-mail: investor.relations@cosmofirst.com, Website: www.cosmofirst.com



SCAN HERE
For detailed results

“Driving momentum through perseverance and growth, our journey embodies resilience and upward progress. With strategic focus and dedication, we continue to achieve success, creating lasting value for stakeholders.”

- Ashok Jaipuria

OUR BUSINESSES:

COSMO FILMS
Engineered to Enhance

COSMO PLASTECH
Designed to protect

COSMO SUNSHIELD
Engineered to protect

COSMO SPECIALTY CHEMICALS
Engineered to enhance

ziggy
For Happy Pats